The Academic
International Journal of Multidisciplinary Research

An Online Peer Reviewed / Refereed Journal
Volume 4 | Issue 1 | January 2026
ISSN: 2583-973X (Online), SJIF IF: 5.6
Website: www.theacademic.in

विकसित भारत @2047 के लक्ष्यों के अनुरूप चुनावी घोषणा पत्र की नीतिगत प्राथमिकताएं

अखिलेश कुमार झा

पी-एच. डी. शोधार्थी, राजनीति विज्ञान विभाग, महात्मा गांधी केन्द्रीय विश्वविद्यालय, मोतिहारी, बिहार।

DOI : https://doi.org/10.5281/zenodo.18713901

ARTICLE DETAILS

Research Paper

Accepted: 28-01-2026

Published: 10-02-2026

Keywords:

विकसित भारत @2047, चुनावी घोषणा पत्र, नीतिगत प्राथमिकताएं , आर्थिक समृद्धि।

ABSTRACT

'विकसित भारत @2047' भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय युवाओं के समक्ष प्रस्तुत किया गया विजन है। इसके अलावा भारतीय युवा से इस विषय पर 'विचार' आमंत्रित किए है इसे 'वॉयस ऑफ यूथ' कहा गया । इसके अंतर्गत आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर भारत को एक विकसित राष्ट्र के रूप में स्थापित करने की मनोरम स्वप्न को साकार करने की संकल्प लिया हैं। विकसित भारत @2047 कार्य-योजना के अनुसार वर्ष 2047 तक भारत की अर्थव्यवस्था $30 ट्रिलियन होगी। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है तथा वर्ष 2047 तक सबसे ज्यादा कार्यबल प्रदाता देश बनने जा रहा है। वर्तमान में भारत विश्व का पाँचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश है। भारत कोविड -19 वैश्विक आर्थिक मंदी में भी अपनी विकास दर को स्थिर रखने में कामयाब रहा है। विकसित भारत @2047 के चार आधार स्तम्भ है महिला, किसान, युवा शक्ति तथा गरीब (श्रम शक्ति)। इसके माध्यम से इन सभी के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत की कल्पना बहुत सकारात्मक है। इस राह में भारत के सामने कई चुनौतियाँ है जैसे वर्ष 2047 तक भारत की जनसंख्या 1.65 अरब हो जाएगी, इतनी बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार उपलब्ध कराने की चुनौतियाँ होगी। विकसित देश अपनी जीडीपी का 4.5 फीसद शोध और नवाचार

पर व्यय करते है। भारत अभी अपनी जीडीपी का 0.59 प्रतिशत ही शोध व नवाचार पर व्यय कर रहा है। विकसित देश के नागरिक की प्रति व्यक्ति आय 15000-16000 डॉलर है जबकि भारत के नागरिकों की आय 2500 डॉलर है। विकसित भारत 2047 एक समृद्ध भारत की परिकल्पना है। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक महत्त्वपूर्ण काल है जब देश अपनी पहचान, विकास और भविष्य की दिशा पुनः परिभाषित करने की प्रक्रिया में है। इस संदर्भ में, चुनावी घोषणा पत्र की नीतिगत प्राथमिकताएँ विकसित भारत के लक्ष्यों की प्राप्ति में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इस शोध पत्र के माध्यम से हम चुनावी घोषणा पत्र का अर्थ, विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों को जानने का प्रयत्न करेंगें, चुनावी घोषणा पत्रों में नीतिगत प्राथमिकताओं का विश्लेषण करेंगे, जो विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप हैं। यह शोध पत्र केवल राजनीतिक दृष्टि से ही महत्त्वपूर्ण नहीं है बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक समृद्धि के दृष्टिकोण से महत्त्वपूर्ण है। अध्ययन में आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, शिक्षा-स्वास्थ्य डिजिटल परिवर्त्तन, पर्यावरणीय सतता और सुशासन जैसे आयामों को प्रमुखता दी गई है। इस शोध पत्र में हम चुनावी घोषणा पत्र के महत्व का भी विश्लेषण करेंगे।

1. विषय परिचय

'विकसित भारत @2047' भारत सरकार का एक विजन है, जिसका उद्देश्य वर्ष 2047 तक भारत को विकसित भारत के रूप में स्थापित करना है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2021 को स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिल्ली के लाल किला से अपने भाषण में कहा कि वर्ष 2047 जब भारत आजादी का स्वर्ण जयंती (100 साल) मना रहा होगा, तब भारत, विकसित भारत के ध्वज के नीचे स्वतंत्रता दिवस की ध्वजारोहण करेगा। उन्होंने कहा कि 'अमृत काल' काल का लक्ष्य एक ऐसे भारत का निर्माण करना है, जहाँ सुविधाओं का स्तर गाँव और शहर को बांट न रहा हों; जहाँ सरकार नागरिकों के जीवन में अनावश्यक हस्तक्षेप न करें; जहाँ दुनिया का हर आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद हो। इन लक्ष्यों को प्राप्ति हेतु उन्होंने ने नारा दिया "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। वर्ष 2022 के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में इस बात का उल्लेख किया कि

किस प्रकार संपूर्ण भारत ने आजादी का अमृत महोत्सव मनाया और अमृत काल के पाँच प्राण को साझा किया : विकसित भारत का लक्ष्य, औपनिवेशिक मानसिकता के किसी प्रतीक को मिटाना, अपनी जड़ों और एकता पर गर्व करना, नागरिकों में कर्तव्य की भावना पोषित करने तथा उन्होंने ने कहा कि नई संभावनाओं को पोषित करने, नए संकल्पों को साकार करने आत्मविश्वास के साथ बढ़ने का आग्रह किया तथा देश को आगे ले जाने के सामूहिक प्रयासों और टीम को रेखांकित किया। इस तरह से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने विकसित भारत की नींव रखी और भारत को वर्ष 2047 तक विकसित भारत के रूप में स्थापित करने का संकल्प लिया। वित्तमंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन ने केन्द्रीय बजट वर्ष 2022-23 को पेश करते समय अपने दिए गए बजट भाषण में प्रधानमंत्री श्री मोदी के दृष्टिकोण को स्पष्ट करते हुए कहा कि सरकार का लक्ष्य है :

- वृहद- आर्थिक स्तर के विकास फोकस को सूक्ष्म-आर्थिक स्तर के सर्व-समावेशी कल्याण फोकस के साथ लागू करना।
- डिजिटल अर्थव्यवस्था और फिनटेक, प्रौद्योगिकी-सक्षम विकास, ऊर्जा परिवर्तन और जलवायु कार्रवाई को बढ़ावा देना ।
- सार्वजनिक पूंजी निवेश के साथ निजी निवेश को भी बढ़ावा देना ।
- विकसित भारत के रोड-मैप तैयार करने की जिम्मेदारी भारत के शीर्ष थिंक टैंक नीति आयोग को सौंपी हैं।

भारत के स्वतंत्रता के सौ वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर, वर्ष 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र के तौर पर स्थापित करने की परिकल्पना के लिए चुनावी घोषणा पत्रों में नीतिगत प्राथमिकतों का विश्लेषण करना महत्त्वपूर्ण है। यह अध्ययन न केवल राजनीतिक दृष्टिकोण में महत्त्पूर्ण, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक दृष्टिकोण से भी एक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है।

2. विकसित भारत @2047 क्या है :

'विकसित भारत @2047' अगले 25 वर्षों में भारत के विकास का एक ब्लू प्रिन्ट है अथवा भारत द्वारा अगले 25 वर्ष लक्ष्यों को प्राप्त करने की परियोजना है। इस परियोजना का लक्ष्य भारत को नवाचार एवं प्रौद्योगिकी में विश्व में अग्रणी देश के रूप में स्थापित करना है जो मानव विकास एवं सामाजिक कल्याण के मामले में भी एक मॉडल देश के रूपं में प्रस्तुत करना तथा जो पर्यावरणीय संवाहनीयता का प्रबल समर्थक होगा। विकसित भारत परियोजना देश के योजनाओं, प्राथमिकताओं और लक्ष्यों के निर्माण

में देश के युवाओं के सक्रिय रूप से सहभागी बनाने का एक मंच प्रदान करता है। जहाँ युवा कार्यशाला, सम्मेलन तथा संगोष्ठी के माध्यम से अपने विचार को साझा करेंगे। भारत कोविड -19 वैश्विक आर्थिक मंदी में भी अपनी विकास दर को स्थिर रखने में कामयाब रहा है। विकसित भारत @2047 के चार आधार स्तम्भ है महिला, किसान, युवा शक्ति तथा गरीब (श्रम शक्ति)। इसके माध्यम से इन सभी के सर्वांगीण विकास का लक्ष्य रखा गया है। भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है तथा वर्ष 2047 तक सबसे ज्यादा कार्यबल प्रदाता देश बनने जा रहा है। विकसित भारत के पाँच विषय है :

- सशक्त नागरिक (स्वस्थ, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, खेल, संस्कृति एवं कल्याणकारी समाज)
- संपन्न और टिकाऊ अर्थव्यवस्था (उद्योग, ऊर्जा, कृषि, बुनियादी ढांचा, सेवाएं, ग्रीन अर्थव्यवस्था और सिटी
- नवाचार, विज्ञान और प्रद्योगिकी(अनुसंधान और विकास, स्टार्ट अप और डिजिटल)
- सुशासन एवं सुरक्षा।
- वैश्विक नेतृत्व

3. विकसित भारत की अवधारणा एवं लक्ष्य

उच्च और सतत आर्थिक वृद्दि प्राप्त करने के लिए विकसित भारत @2047 का उद्देश भारत की अर्थव्यवस्था को वर्ष 2047 तक 30 ट्रिलियन अमेरिकी डालर करना । वर्तमान में भारत की अर्थव्यवस्था 3.7 ट्रिलियन डालर की है। रेटिंग एजेंसी "s&p" का अनुमान है कि भारत की नॉमिनल जीडीपी वर्ष 2023 में 3.7 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से बढ़कर वर्ष 2030 तक 7.3 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर हो जाएगी। वर्ष 2047 में भारत के निर्यात का मूल्य 8.67 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा जबकि आयात का मूल्य 12.12 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर होगा। भारत की औसत जीवन प्रत्याशा 67.2 (वर्ष 2021 में) से बढ़कर 71.8 हो जाएगी और साक्षरता दर 77.8 प्रतिशत से बढ़कर 89.8 प्रतिशत हो जाएगी ।

विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप सामाजिक समावेशन और सामान अवसर प्रदान करने के लिए भारत प्रयासरत है और इसके लिए आवश्यक कदम भी उठाये जा रहे है। इस संकल्पना में सामाजिक समावेशन और अवसर की समानता में न केवल आर्थिक और सामाजिक असमानता को समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है बल्कि प्रत्येक स्तर पर समावेशी विकास को प्रोत्साहित करने की आवश्यकता पर जोड़ दिया जा रहा है। भारतीय संविधान में उपबंधित अवसर की समानता का अधिकार देश के प्रत्येक

वर्ग, समुदाय, लिंग और आयु वर्ग के नागरिक को सामान रूप से प्रदान करने के उद्देश्य से नीतियों का निर्माण करने की आवश्यकता है।

विकसित भारत के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए विकास के आधारभूत चार स्तंभ : शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत संरचना और आर्थिक विकास आदि जो भारतीय समाज के समग्र विकास की नींव है। इन चार आयामों में सबसे महत्त्वपूर्ण आधारभूत संरचना को मजबूत करने की जरूरत है। शिक्षा के क्षेत्र में नई शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत समावेशी, गुणवत्तापूर्ण एवं कौशल युक्त शिक्षा की को मजबूती से लागू करने की आवश्यकता है। हमारी वर्तमान स्वास्थ्य प्रणाली में मूलभूत सुधार की आवश्यकता है। यह सुनिश्चित करना कि स्वास्थ्य सेवाएँ सभी वर्गों के लिए सुलभ हो, हलाकिं भारत सरकार द्वारा 'आयुष्मान कार्ड' के माध्यम से प्रत्येक परिवार को 5 लाख तक मुफ्त स्वास्थ्य सेवा की व्यस्था की गई है।

आर्थिक उन्नति के लिए यह आवश्यक है कि समावेशी विकास, सूक्ष्म, लघु एवं कुटीर, और माध्यम उद्द्योगो को प्रोत्साहित किया जाए। सरकार द्वारा इन उद्द्योगों को नवीनतम तकनीक से जोड़ा जाए। इसके साथ ही निवेश और और संसाधनों का न्यायसंगत आवंटन किया जाए तथा युवा उद्दमी के लिए अवसर को सृजित किया जाए। इन चारों आयामों का समग्र और संतुलित कार्यान्वयन करने से भारत के सतत, समुन्नत और आत्मनिर्भर बनाने में सहायक सिद्ध होगा।

उपरोक्त लक्ष्य तभी साकार होंगे जब राजनीतिक दल की नीतिगत प्राथमिकताएँ इन आयामों से समन्वित होंगे।

4. चुनावी घोषणा पत्र अर्थ और अवधारणा

चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के नीतियों और कार्यक्रमों का एक लिखित दस्तावेज है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल मतदाताओं के विश्वास को प्राप्त करने का प्रयास करता है। चुनावी घोषणा पत्र एक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज है जिसमें राजनीतिक दल द्वारा अपने आगामी चुनाव के प्राथमिक एजेंडे और वादों का उल्लेख करते है। चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक दलों और मतदाताओं के बीच चुनाव के समय संवाद का आधार बनता है। इसके साथ-साथ मतदाताओं के विश्वास का माध्यम भी बनता है। इसका निर्माण राजनीतिक दलों के द्वारा गहन शोध, सर्वेक्षण और राजनीतक विमर्श के द्वारा किया जाता है। चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक दलों के राजनीतिक प्रतिबद्धता और उत्तरदायित्व का प्रतीक बन जाता है क्योंकि यह मतदाताओं के आकांक्षाओं और विश्वास का आश्वासन पत्र बन जाता है। इसके माध्यम से जनता अपने उम्मीदवारों या दलों के नीतियों और योजनाओं के प्रति जागरूक होता है और

इससे प्रभावित होकर मतदान कर करता है। चुनावी घोषणा पत्र का विश्लेषण करके यह समझना में आसनी होती है कि किसी भी राजनीतक प्रणली में राजनीतिक तत्व कैसे अपना जनाधार बढ़ाते है। चुनावी घोषणा पत्र को शासन का रोडमैप के रूप में देखा जाता है।

चुनावी घोषणा पत्र राजनीतिक संचार का साधन होता है जिसके माध्यम से राजनीतिक दल मतदाता से संवाद स्थापित करता है। डेविड ईस्टन के अनुसार 'घोषणाएं जनता की मांगों और राजनीतिक प्रणाली की प्रतिक्रियाओं के बीच सेतु का कार्य करता है'। भारत में चुनावी घोषणा पत्र मतदान व्यव्हार को प्रभावित करता है। यह सरकार की प्राथमिकताओं के एक दिशा प्रदान करता है तथा राजनीतिक दलों को जनता के प्रति जबावदेह बनता है।

वर्तमान में चुनावी घोषणा पत्र में राजनीतिक पार्टियों द्वारा लोकलुभावन घोषणाओं को अधिक स्थान दिया जाता है। जो विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप नहीं है। जो देश की आर्थिक को गतिहीन बनता है तथा राजनीतिक पार्टियाँ मतदाता को तरह-तरह का प्रलोभन देकर अपने पक्ष में मतदान करने के लिए प्रभावित करती है जोकि लोकतंत्र के सिद्धांत के विरुद्ध है। सर्वोच्च न्यायलय द्वारा लोक लुभावन घोषणा पर कई बार टिप्पणी की है तथा चुनाव आयोग को राजनीतिक दलों से विचार-विमर्श कर चुनावी घोषणा के संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने का निर्देश दिया था। किन्तु चुनाव आयोग द्वारा तैयार किया गया निर्देश राजनीतिक दलों द्वारा लोकलुभावन घोषणा या अतार्किक वादों करने पर अंकुश के लिए अपर्याप्त है।

5. विकसित भारत के अनुरूप चुनावी घोषणापत्र में नीतिगत प्राथमिकताएँ

5.1 आर्थिक विकास और आत्मनिर्भरता

चुनावी घोषणा पत्र में आर्थिक वृद्धि, औद्योगिकीकरण, एमएसएमई सुदृधीकरण, स्टार्ट-अप, कौशल विकास और रोजगार सृजन को प्रथ्मिकीता दी जानी चाहिए। आत्मनिर्भर भारत की अवधारणा विकसित भारत 2047 का आधार स्तंभ है। वित्तीय समावेशन को भी चुनावी घोषणा पत्र में स्थान देना चाहिए जिससे कि आर्थिक रूप से वंचित वर्गों को आर्थिक गतिविधियों में सहभागी बनाया जा सके।

5.2 रोजगार, कौशल और युवा नीति

भारत वर्तमान में विश्व के सबसे युवा देशों में से एक है, जिसकी औसत आयु लगभग 29 वर्ष है। भारत की जनसंख्या संरचना में युवा शक्ति (15-29वर्ष) आयु वर्ग के युवा देश की आबादी का सबसे महत्त्वपूर्ण हिस्सा है, जो लगभग 34 प्रतिशत से अधिक सकल राष्ट्रीय आय में योगदान देता है। भारत का यह 'जनसाख्यिकीय लाभांश' भारत को विकसित भारत 2047 के लक्ष्यों प्राप्त करने में अहम भूमिका निभाएगा। किन्तु इसके लिए यह आवश्यक है कि सरकार युवा शक्ति का उपयोग सही दिशा में करें। विकसित भारत का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए युवाओं का कुशल होना आवश्यक है, इसके लिए सरकार को युवाओं को कुशलता की प्रशिक्षण देना, रोजगारपरक शिक्षा, युवा को नई-नई तकनीक जैसे डेटा साइंस, रोबोटिक्स, डेटा मइनिंग, आर्टिफीसियल इंटेलिजेंस आदि का प्रशिक्षण देकर वैश्विक कार्यबल में भारत की हिस्सेदारी बढानी होगी। सरकार को स्थानीय विनिर्माण को बढ़ावा देकर युवा शक्ति को आत्मनिर्भर भारत की ओर अग्रसर करना होगा। भारतीय युवा को अब नौकरी करने वाला न होकर नौकरी देने वाला बनाना होगा, इसके लिए युवा में जोखिम उठाने की शक्ति प्रदान करना होगा तब भारत वर्ष 2047 तक विकसित भारत के श्रेणी में आ सकता है।

5.3 सामाजिक न्याय और समावेशी विकास

विकसित भारत का उद्देश्य मात्र आर्थिक समृद्धि को प्राप्त करना नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय को भी स्थापित करना है, इसके लिए जाति, भाषा, वर्ग, लिंग, जन्म स्थान आधारित विभेद को समाप्त कर सामाजिक समरसता को स्थापित करने की आवश्यकता है। साथ ही वंचित वर्गों का विकास और क्षेत्रीय असमानता को कम करने वाली नीतियों को राजनीतक दलों द्वारा घोषणा पत्र में अनिवार्य रूप से सम्मिलित की जानी चाहिए।

5.4 शिक्षा और स्वास्थ्य

शिक्षा और स्वास्थ्य मानव विकास का आधारभूत तत्व है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा संपूर्ण आबादी को उपलब्ध करने का प्रयास सरकार को करना चाहिए। नई शिक्षा नीति 2020 को लागू कर शीघ्र क्रियान्वयन करना, शोध, नवाचार, रचनात्मकता बढ़ावा देना और प्राथमिक स्वास्थ्य ढाँचे को सुदृढ़ करना घोषणा पत्र में सम्मिलित की जानी चाहिए।

5.5 पर्यावरण और सतत विकास

विकास और पर्यावरण के बीच संतुलन स्थापित करना आवश्यक है। आज विकास की अंधी दौड़ में मानव पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है जिसके दुष्यपरिणाम दिखना आरंभ हो गया है। अतः चुनावी घोषणा पत्र में नवीकरणीय उर्जा, जल संरक्षण नीति, स्वच्छता नीति और जलवायु परिवर्तन का सामना करने की नीतियों को शामिल किया जाना चाहिए।

6. विकसित देश का दर्जा प्राप्त करने के मानक

ऐसे विकास शील या विकसित देश को का कोई सर्वमान्य मानक निर्धारित नहीं है अलग-अलग मानकों पर किसी देश को विकसित या विकास शील देश के रूप में श्रेणीबद्ध किया जाता है। मुख्यतः विकसित देश में स्वास्थ्य, शिक्षा, एवं परिवहन की उन्नत व्यवस्था होती है। जनमानस समृद्ध होते है।

विकसित देश के कुछ सामान्य लक्षण :

- उन्नत विज्ञान तथा तकनीकी द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग।
- वृहत स्तर पर औद्योगीकरण
- कृषि का यंत्रीकरण।
- व्यापारिक आधार पर उद्यानों का विकास।
- उन्नत स्तर पर पशुपालन तथा दुग्ध व्यवसाय का विकास
- विकसित यातायात एवं संचार व्यवस्था।
- प्रतिव्यक्ति आय और राष्ट्रीय आय।
- महिलाओं की स्थिति इत्यादि।

7. विकसित भारत की दिशा में भारत की उपलब्धियाँ

भारत ने विकसित भारत की दिशा में कई मुकाम भी हासिल की हैं जैसे भारत ब्रिटेन को पीछे छोड़कर दुनिया की पाँचवीं बड़ी अर्थव्यवस्था बन गई है, भारत ने चाँद और मंगल पर अपने अंतरिक्ष यान भेजे, भारत ने मेक इन इंडिया के माध्यम से भारत में रक्षा उपकरण बनाने शुरू किए। भारत ने खाद्य सुरक्षा को सफलतापूर्वक लागू किया। भारत अपने नागरिकों को स्वस्थ बीमा के अंतर्गत लगभग 59 करोड़ नागरिक को आयुष्मान कार्ड दिए जिसमें हर कार्ड धारक को 5 लाख तक का मुफ़्त इलाज हो सकते है। आयुष्मान कार्ड के तहत देश में 27000 सार्वजनिक एवं निजी अस्पताल में नागरिक इलाज करवा सकता है । भारत ने संपूर्ण भारत में बिजली, पानी और सड़क पहुंचाया है। भारत वैश्विक मंदी चुनौती के बीच वित्त वर्ष 2021-22 में 83.57 अरब डालर का रिकार्ड एफडीआई प्राप्त किया है। भारत का उत्पाद

एवं सेवा निर्यात करीब 668 अरब के ऐतिहासिक स्तर को पहुँच गया। यह आकड़े इस बात की ओर संकेत करता है कि भारत अब निर्यात अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर है।

8. चर्चा

कोई भी लक्ष्य प्राप्ति हेतु यह आवश्यक है, सबसे पहले उस लक्ष्य को निर्धारित करें। उस लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु एक स्पष्ट दृष्टिकोण और रणनीति तैयार की आवश्यकता है। विकसित भारत 2047 भारत की समृद्धि हेतु एक दृष्टिकोण और रणनीति है। चुनावी घोषणा पत्र में नीतिगत प्राथमिकताएँ इस दिशा में संकेत स्वरुप एक महत्त्वपूर्ण दिशा-निर्देश है, जिसके माध्यम से विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। इसके लिए चुनावी घोषणा पत्र में राजनीति दलों को लोकलुभावन घोषणा से बचना होगा। इसके जगह शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आधारभूत संरचना का विकास, डिजिटल भारत का निर्माण, युवा को कुशलता की प्रशिक्षण, युवा को नए स्टार-अप शुरू करने हेतु प्रोत्साहन, समावेशी विकास, सामाजिक न्याय, स्मार्ट सिटी, पर्यावरण संरक्षण, सतत विकास, नई-नई तकनीक का प्रशिक्षण इत्यादि नीतिगत प्राथमिकताओं को राजनीतिक दलों द्वारा अपने चुनावी घोषणा पत्र में शामिल करने करें तथा अपने घोषणा पत्र में उल्लेखित घोषणाओं को सरकार में आने के उपरांत पूर्ण करने का हर संभव प्रयास करें, जिससे वर्ष 2047 तक भारत की विकसित भारत की परिकल्पना पूर्ण होने में सहायक सिद्ध हो

वर्तमान में अधिकांश राजनीतिक दल अपने चुनावी घोषणा पत्र में विकसित भारत 2047 से संबंधित लक्ष्यों को शामिल करते है किन्तु उनके अधिकांश घोषणा अल्पकालिक होते है तथा लोक लुभावन से प्रेरित होते है। उनके द्वारा किये गए घोषणा का कोई भी न तो रोडमैप होता है, न ही कोई समय सीमा निर्धारित होती है। साथ ही चुनावी घोषणाओं को पूर्ण करने के लिए वित्तीय संसाधन के स्त्रोत का उल्लेख भी नहीं होता है। राजनीतक दलों की इस स्थिति के कारण मतदाता भ्रमित हो जाते है और राजनीतिक दलों की घोषणाओं की विश्वसनीयता पर संदेह बना रहता है।

9. निष्कर्ष

यह कहा जा सकता है कि वर्तमान में राजनीतक दलों के चुनावी घोषणा पत्र की नीतिगत प्राथमिकता आंशिक रूप से विकसित भारत के लक्ष्यों के अनुरूप है। आवश्यकता इस बात की है कि राजनीतिक दलों द्वारा चुनावी घोषणा पत्रों का निर्माण राष्ट्रहित को केंद्र में रखकर करें। चुनावी घोषणा पत्र में महिला, किसान, युवा शक्ति तथा गरीब चारों वर्गों को प्राथमिकता दें। इन्हे ऐसे अतार्किक घोषणा से बचना चाहिए, जिसके पूर्ण होने की संभावना न हो। नीति आधारित और प्रमाण आधारित घोषणाओं को

प्राथमिकता दें। दलगत राजनीतिक लाभांश से ऊपर उठकर घोषणा पत्र तैयार करें। भारत को विकसित भारत बनने के लिए लगभग 8 प्रतिशत से अधिक का विकास चाहिए, यह तभी संभव है जव राजनीतिक दलों द्वारा अपने घोषणा पत्र में नीतिगत प्राथमिकितायें जैसे समावेशी विकास, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवा, रोजगार सृजन, वित्तीय समावेशन, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय, सांस्कृतिक संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, संस्थागत सुधार आदि तत्वों का समावेश करेगा और सत्ता में आने के उपरांत उसे पूर्ण करेगा, तभी विकसित भारत 2047 की परिकल्पना साकार होगा।

10. सुझाव

- चुनावी घोषणा पत्र तैयार करने हेतु राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर एक दिशा निर्देश।
- चुनावी घोषणा पत्र निगरानी समिति का गठन करना।
- राजनीतिक दलों द्वारा यदि कोई लोकलुभावन घोषणा की जाती है तो यह बताना अनिवार्य होना चाहिए कि अमुख योजना के लिए धन कहा से और कैसे आयेंगे।

संदर्भ सूची

- भार्गव, डॉ. प्रभा(2006). चुनावी घोषणा पत्र : सिद्धांत एवं स्थिति. जयपुर: राजस्थान हिंदी ग्रन्थ अकादमी.
- Verma, S., & Gupta, S. (2021). Enhancing employability through vocational education: A case study of skill development initiatives in Viksit Bharat. Journal of Education and Work, 34(1), 1-18
- https://hindi.eci.gov.in/election-manifestos/
- https://www.nextias.com/ca/editorial-analysis-hindi/16-09-2024/indias-path-to-2047-key-parameters-and-challenges-2
- कुमार, पवन & कुमारी, मीरा (2024). विकसित भारत@2047. शोध श्री - एन इंटरनेशनल मल्टीडिसप्लिन जर्नल. वोल्यूम 03. इशू 02, पेज 253-259.
- https://cleartax.in/s/viksit-bharat-2047
- 7.https://books.google.co.in/books?id=qs8AEQAAQBAJ&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false